कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है। यह रा.रा.क्षे.दि.स. के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करता है और इसके राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करता है, इसकी ऋण स्थिति का आकलन करता है, राजकोषीय दायित्व संबंधी विधियों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतकों के प्रति इसके निष्पादन की तुलना करता है।

आर्थिक विकास और स.रा.घ.उ.

रा.रा.क्षे. दिल्ली की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 12.15 लाख करोड़ के स.रा.घ.उ. के साथ पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.17 *प्रतिशत* की अच्छी वृद्धि दर्ज की। रा.रा.क्षे. दिल्ली ने 2024-25 में भारत के स.घ.उ. में 3.67 *प्रतिशत* का योगदान दिया।

2015-2025 की अवधि के दौरान सीएजीआर द्वारा मापी गई प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि (6.39 *प्रतिशत*) इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (8.14 *प्रतिशत*) में वार्षिक वृद्धि से कम रही। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. जो 2015-16 में देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. से 177.07 *प्रतिशत* अधिक था, 2024-25 के अंत में घटकर 135.34 *प्रतिशत* हो गया। यह देश के बाकी हिस्सों की तुलना में रा.रा.क्षे.दि. के आर्थिक विकास की धीमी गति को दर्शाता है।

राजस्व प्राप्तियां

यह पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियों में 9.57 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है, जो उच्च कर संग्रहण, विशेष रूप से जीएसटी के कारण है। तथापि, गैर-कर राजस्व वृद्धि ऋणात्मक (-11.04 *प्रतिशत*) थी और केंद्र से प्राप्त अनुदान में गिरावट आई। रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने राजस्व निष्पादन में सुधार

हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सहायता अनुदान पर निर्भरता में काफी गिरावट आई है।

राजस्व व्यय

रा.रा.क्षे.दि.स. के व्यय में राजस्व व्यय (88.38 *प्रतिशत*) की उच्च वृद्धि प्रबल थी, विशेष रूप से प्रतिबद्ध लागत और सब्सिडी के कारण पूंजी निवेश के लिए सीमित राजकोषीय गुंजाइश थी। 2015-25 की अवधि के दौरान सब्सिडी में ₹ 3,222 करोड़ (172.48 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से विद्युत सब्सिडी में ₹ 2,033 करोड़ (128.83 *प्रतिशत*) तक की वृद्धि के कारण थी।

पूंजीगत व्यय

2015-25 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में कुल व्यय के 7 *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* तक की गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, जो अवसंरचना निवेश और पूंजी निर्माण में बाधाओं को दर्शाता है।

पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि के बजाय गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और अवसंरचना में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश में कमी का संकेत देता है। वर्ष 2021-22 में, यह ₹ 8,311 करोड़ था जो क्रमशः घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,695 करोड़ हो गया। पिछले कुछ वर्षों में, अर्थव्यवस्था के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का समग्र हिस्सा घटता जा रहा है, जिससे पता चलता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने विकास उद्देश्यों के अनुरूप परिसंपत्ति निर्माण को लगातार प्राथमिकता नहीं दी है। यह पैटर्न अवसंरचना और विकास कार्यक्रमों में निरंतर निवेश के लिए सीमित राजकोषीय स्थान का संकेत देता है, जो संभावित रूप से दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सेवा वितरण को प्रभावित करता है।

क्षेत्रीय व्यय

क्षेत्र-वार व्यय पैटर्न दर्शाता है कि व्यय में सामाजिक सेवाएं प्रबल हैं (कुल व्यय का 49 से 55 *प्रतिशत*) जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे कल्याणकारी और सामाजिक विकास कार्यक्रमों पर सरकार के विशेष ध्यान को दर्शाता है। यद्यपि सामाजिक कल्याण पर यह विशेष ध्यान उल्लेखनीय है,

परंतु दीर्घकालिक विकास को कम किए बिना ऋण दायित्वों और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं दोनों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए संसाधन आबंटन को अनुकूलित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

स्थानीय निकायों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के संबंध में, हमने देखा कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को 6 से 27 *प्रतिशत* तक की बहुत कम वित्तीय सहायता दी गई थी, जो यह दर्शाता है कि 2015-2025 के दौरान 73 से 94 *प्रतिशत* तक की अधिकांश सहायता स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के दिन-प्रति-दिन के व्यय के लिए दी जा रही थी।

निवेश

सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश ₹ 18,492 करोड़ (2015-16) से बढ़कर ₹ 21,810 करोड़ (2024-25) हो गया है, परंतु रिटर्न नगण्य (1 *प्रतिशत* से कम) बना हुआ है, जो उधार की 7.6-8.7 *प्रतिशत* लागत से बहुत कम है, जो सार्वजनिक धन के अकुशल उपयोग और राजकोषीय तनाव को दर्शाता है। कुछ संस्थाएं लाभांश की घोषणा करती हैं, जब कि निष्क्रिय या अलाभकारी इकाइयों में बड़ी रकम अवरुद्ध रहती है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप एक प्रभावी लाभांश नीति के अभाव और कमज़ोर विभागीय निगरानी के कारण, अनुपालन की स्थिति खराब है। रा.रा.क्षे.दि.स. को रिटर्न में सुधार और राजकोषीय भार को कम करने के लिए अलाभकारी संस्थाओं की व्यवहार्यता की समीक्षा करने, विनिवेश पर विचार करने और लाभांश घोषणाओं को लागू करने की आवश्यकता है।

ऋण संधारणीयता

कुल मिलाकर, रा.रा.क्षे.दि.स. का ऋण प्रक्षेप-पथ राजकोषीय तनाव का कम जोखिम, अनुशासित उधारी और अनुकूल संधारणीयता संकेतकों को दर्शाता है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है कि

उधारी मुख्य रूप से चुकौतियों द्वारा अवशोषित होने के बजाय विकास बढ़ाने वाले निवेश का समर्थन करें।

अतः, संभावित विकास को प्राप्त करने और उसमें तेज़ी लाने के लिए भौतिक और मानव पूंजी निर्माण में निरंतर निवेश व्यय के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त कर संसाधन मुख्य रूप से बेहतर कर संग्रहण तथा गैर-कर राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों के साथ-साथ अनुपालन बढ़ाने के लिए प्रवर्तन को मज़बूत करने से आने चाहिए।

निष्कर्ष

दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वृद्धि, बेहतर व्यय नियंत्रण और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। समय पर लेखांकन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए। अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

****